दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३४२ वा | शनिवार १९ जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

जनसुरक्षा विधेयक पर सरकार ने विपक्ष के साथ की धोखाधड़ी-जयंत पाटील

रिपोर्ट: ज़मीर क़ाज़ी, मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक दल के नेता जयंत पाटील ने शुक्रवार को सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि जनसुरक्षा विधेयक के संदर्भ में सरकार ने विपक्ष की धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को दरकिनार कर दिया गया और सरकार ने पहले जो वादे किए थे, उन्हें अंतिम विधेयक में शामिल नहीं किया।

पाटील ने कहा, यह मेरा विधानमंडल में छत्तीसवां वर्ष है। इन ३६-३७ वर्षों में मैंने कभी भी ऐसे अवांछनीय तत्वों को सदन या उसके परिसर में आते नहीं देखा था, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। कुछ विधायकों के संपर्क अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से बढ़ते जा रहे हैं, जो विधायक से पहले ही परिसर में दाखिल हो जाते हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने यह बात विधानमंडल के पावसाळी अधिवेशन के समापन पर विधान भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में कही। इस अवसर पर उनके साथ विधायक जितेंद्र आव्हाड भी उपस्थित थे।

पाटील ने बताया कि, जब यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया था, उस समय हमने कई सुझाव दिए थे। सरकार ने उन सुझावों को स्वीकार करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन जब विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, तब उसमें हमारे द्वारा सुझाए गए अधिकांश बिंदु शामिल नहीं थे। सिर्फ ३-४ सुझाव ही लिए गए। यह एक तरह से विपक्ष के साथ धोखा है।

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आज विपक्ष के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से भेंट कर इस विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की है और सभी संदिग्ध प्रावधानों की जानकारी उन्हें दी गई है।

पूर्व मंत्री जयंत पाटील ने कर्जमाफी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब हमने बिना किसी समिति के सीधे कर्जमाफी लागू की थी। लेकिन अब की सरकार सिर्फ समिति बनाकर समय बर्बाद कर रही है, जो किसानों के साथ अन्याय है।

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर सरकार को सच में कर्जमाफी करनी होती, तो वो इसे २०२९ के चुनावों से ठीक पहले करती। अभी सिर्फ समिति बनाने की बात कहकर स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

जयंत पाटील ने स्पष्ट कहा कि सरकार की यह रणनीति विपक्ष को भ्रमित करने और जनता को गुमराह करने की साजिश है, लेकिन विपक्ष इसे कभी सफल नहीं होने देगा।

ना.पंकजा मुंडे के कार्य की तेज़ रफ्तार

राज्य में ३५७ स्थानों पर पशु चिकित्सालयों को मिलेंगी नई इमारतें; ज़िला योजना से होंगे ४५८ करोड़ रुपये खर्च

मुंबई, १८ जुलाई संवाददाता

राज्य की पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजा मुंडे की योजनाबद्ध और गतिशील कार्यशैली के कारण महाराष्ट्र राज्य के ३५७ स्थानों पर पशु चिकित्सालयों को नई इमारतें प्राप्त होंगी। इन इमारतों के निर्माण, दवाखानों की मरम्मत, शौचालय निर्माण और उपकरणों की खरीदी के लिए ज़िला वार्षिक योजना के तहत कुल ४५८ करोड़ ४१ लाख ३४ हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है।

पर्यावरण और पशुसंवर्धन विभाग का कार्यभार सँभालने के बाद से ना. पंकजा मुंडे ने एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कार्य में तीव्रता दिखाई है। पशुसंवर्धन को कृषि व्यवसाय का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बने- इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब राज्यभर में पशु चिकित्सालयों को नई इमारतें प्रदान करने का निर्णय भी उन्होंने लिया है।

इस निर्णय के अंतर्गत राज्य के सातों राजस्व विभागों के कुल ३४ जिलों में ३५७ स्थानों पर पशु चिकित्सालयों को नई इमारतें मिलेंगी। इन इमारतों के निर्माण के लिए २८७ करोड़ ७६ लाख ४४ हजार रुपये, मरम्मत कार्यों के लिए १२१ करोड़ ११ लाख ८२ हजार रुपये, शौचालय निर्माण हेतु २५ करोड़ १७ लाख २० हजार रुपये तथा उपकरणों की खरीदी के लिए २४ करोड़ ३५ लाख ८८ हजार रुपये की निधि निर्धारित की गई है। यह संपूर्ण कार्य वर्ष २०२५-२६ की ज़िला वार्षिक योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए हैं।

बीड़ ज़िले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल २४ नई इमारतों के निर्माण के लिए ९ करोड़ ४० लाख रुपये की निधि स्वीकृत की गई है।

राज्य के विभिन्न विभागों में जिन जिलों में पशु चिकित्सालयों के लिए नई इमारतें प्रस्तावित की गई हैं, उनकी विभागवार संख्या इस प्रकार है:

मुंबई विभाग (ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) - १३ स्थान

पुणे विभाग (पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर) - १२५ स्थान

नाशिक विभाग (नाशिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर) - ५५ स्थान

छत्रपति संभाजीनगर विभाग (छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड़) - ५१ स्थान

लातूर विभाग (लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, हिंगोली) - ३९ स्थान

अमरावती विभाग (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ) - ३८ स्थान

नागपुर विभाग (नागपुर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली) - ३६ स्थान

इस प्रकार, कुल ३५७ स्थानों पर पशु चिकित्सालयों की इमारतों के निर्माण हेतु आर्थिक प्रावधान किया गया है।

तो भविष्य में विधानसभा में लाशें गिरेंगी-राज ठाकरे का तीखा हमला

रिपोर्ट: ज़मीर क़ाज़ी, मुंबई

दिनांक: १८ जुलाई

विधान भवन परिसर में सत्ताधारी और विपक्षी विधायकों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई जबरदस्त मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,

ये दृश्य देखकर मेरे मन में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की हालत क्या हो गई है? अगर आज इन लोगों को माफ कर दिया गया तो भविष्य में विधानसभा के भीतर विधायकों की हत्या भी हो सकती है और हमें हैरानी नहीं होगी।

उन्होंने गुरुवार को हुई घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उसे अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच 'द' (पूर्व ट्विटर) पर लिखा -

सत्ता एक साधन होनी चाहिए, साध्य नहीं। लेकिन आजकल लोग सत्ता के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि किसी को भी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, और फिर उन्हीं लोगों से दूसरे दलों के वरिष्ठ नेताओं पर गंदे बयान दिलवाए जाते हैं। फिर उसी सरकार से नैतिकता की बातें सुननी पड़ती हैं, ये पाखंड अब जनता को भी समझ में आने लगा है।

राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से सवाल किया -

महाराष्ट्र किसके हाथों में दे दिया है आपने?

उन्होंने कहा कि हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक विधानसभा सत्र के एक दिन पर कम से कम १.५ से २ करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

क्या यह पैसा व्यक्तिगत छींटाकशी और झगड़े में बर्बाद करने के लिए है? राज्य में हजारों अहम मुद्दे लंबित हैं, सरकारी खजाना खाली पड़ा है, ठेकेदारों का भुगतान रुका है, जिलों को विकास निधि नहीं मिल रही है। यहां तक कि सत्तारूढ़ दलों के विधायक और मंत्री भी पूछ रहे हैं कि विधानसभा सत्र अब महज औपचारिकता बनकर रह गया है क्या?

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और सत्ताधारी दल मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसे सतही मुद्दे उछालते हैं।

राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा -

अगर ऐसे लोगों को अब भी माफ कर दिया गया, तो आगे चलकर यह परंपरा बन जाएगी, और कोई भी विधानसभा में हत्या कर देगा तो हमें आश्चर्य नहीं होगा।

उन्होंने मीडिया से अपील की कि वह इन फालतू विवादों में ना उलझे और सरकार से भी कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो वे अपने लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएं।

राज ठाकरे ने साफ शब्दों में चेताया -

अगर सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, तो मेरे 'महाराष्ट्र सैनिक' इन दुष्ट मराठी विरोधियों को सीधा कर देंगे। फिर हमें नैतिकता की शिक्षा मत दीजिए।

उन्होंने कहा कि अगर मराठी भाषा या मराठी व्यक्ति का अपमान होता है और कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो

मुझे गर्व है कि मेरे महाराष्ट्र सैनिक उस व्यक्ति को करारा जवाब देते हैं। ये किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण नहीं होता, बल्कि यह उनकी भाषा और अस्मिता की रक्षा के लिए होता है।

आखिर में उन्होंने फिर दोहराया

अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमारे सैनिक चुप नहीं बैठेंगे - और तब हमें ज्ञान मत दीजिए।

मिल्लिया महाविद्यालय में 'करियर कट्टा' कार्यक्रम आयोजित, प्रेरणादायक छात्र संवाद सत्र संपन्न

बीड़: संवाददाता

यहां के मिल्लिया कला, विज्ञान एवं प्रबंधन महाविद्यालय में 'करियर कट्टा' उपक्रम के अंतर्गत एक प्रेरणादायक छात्र संवाद सत्र का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मोहम्मद इलयास फाज़िल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध करियर मार्गदर्शक श्री यशवंत शितोळे उपस्थित रहे।

श्री शितोळे ने विद्यार्थियों को विभिन्न करियर अवसरों, योजना निर्माण, और सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता पर गहराई से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा, उद्यमिता और कौशल विकास जैसे विषयों पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी शंकाएँ पूछीं, जिनका श्री शितोळे सर ने संतोषजनक उत्तर दिया। इस कार्यक्रम में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बीसीए एवं अन्य शाखाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस संवाद सत्र से छात्रों को करियर की स्पष्ट दिशा प्राप्त हुई और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद इलयास फाज़िल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि छात्रों को 'करियर कट्टा' उपक्रम के अंतर्गत आयोजित हर कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि यह उनके सर्वांगीण विकास के लिए लाभकारी है और इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कार्यक्रम का सूत्रसंचालन बीएससी की छात्रा कु. सभा फातिमा ने किया तथा आभार प्रदर्शन शेख जशनैध ने किया। छात्रों ने प्रतिक्रिया दी कि 'करियर कट्टा' जैसे उपक्रमों से महाविद्यालयीन वातावरण में सकारात्मकता और दिशा प्राप्त होती है। इस अवसर पर डॉ. दत्ता नरसाळे, डॉ. रविंद्र काले, प्रा. डॉ. कुटे मैडम, डॉ. भालेराव, डॉ. सावते, डॉ. असीफ इकबाल, डॉ. शेख हुसैन इमाम, शिक्षकगण व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सांसद बजरंग सोनवणे पहुँचे तहसील कार्यालय, वहीं लगाया जनता दरबार

वडवणी के नागरिक निवेदन लेकर पहुंचे, तुरंत मिली सुनवाई

केज, १८ जुलाई संवाददाता

सांसद बजरंग सोनवणे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ जनता दरबार अपने आप लग जाता है - इस बात का उदाहरण एक बार फिर १८ जुलाई को देखने को मिला, जब वे वडवणी तहसील कार्यालय पहुँचे। जैसे ही स्थानीय लोगों को उनकी तहसील में उपस्थिति की जानकारी मिली, वडवणी तालुका के कई गांवों के नागरिक अपनी समस्याओं और निवेदन के साथ तहसील कार्यालय पहुँच गए। परिणामस्वरूप, उसी जगह पर एक अनौपचारिक जनता दरबार लग गया।

सांसद सोनवणे जिला स्तर पर विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार ईमानदारी से प्रयासरत हैं। वे प्रत्येक तालुका में विकास कार्यों और आम नागरिकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी क्रम में १८ जुलाई को उन्होंने वडवणी तहसील कार्यालय में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन,

तहसीलदार, गटविकास अधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान जब वे विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे, उसी समय देवळा, चिंचोटी और आसपास के गांवों के नागरिक बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुँच गए। तब वहीं पर सांसद सोनवणे ने जनता दरबार लगाकर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके निवेदन भी स्वीकार किए।

देवळा और चिंचोटी गांवों में कई वर्षों से अधूरे पड़े सड़क निर्माण के मुद्दे को नागरिकों ने प्रमुखता से उठाया। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सांसद सोनवणे ने तहसीलदार को उसी समय सड़क से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देकर हल करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा वडवणी तालुका से संबंधित रेलवे सेवा, फसल बीमा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। साथ ही सांसद सोनवणे ने ज्ञानेश्वरी मुंडे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उस पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश जिलाधिकारी से की।

इस तरह, सांसद सोनवणे ने एक बार फिर अपने सक्रिय और जनसंपर्कशील नेतृत्व की मिसाल पेश की।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

राज्य के महत्त्वाकांक्षी आधारभूत प्रकल्पों को गति, अपराधों पर लगाम-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रिपोर्ट: ज़मीर क़ाज़ी, मुंबई

महाराष्ट्र में मेट्रो, हवाई अड्डे, रेलवे, टनल, सी-लिंक और कॉरिडोर जैसे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इन आधुनिक परियोजनाओं से शहरी और ग्रामीण विकास को बल मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में कानून-व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो सका है।

वे विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र विधानमंडल नियम २९२ के अंतर्गत चर्चा का उत्तर दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि-

साल २०२३ की तुलना में २०२५ में अब तक कुल ११,६५९ अपराधों में कमी दर्ज की गई है। गंभीर अपराधों में भी गिरावट आई है।

साइबर अपराधों के खुलासे का प्रतिशत १६% से बढ़कर १९% हो गया है।

आर्थिक धोखाधड़ी में जो राशि वसूल की गई, उसका प्रतिशत २०.७५% से बढ़कर ६१% हो गया है।

उन्होंने बताया कि यदि साइबर अपराधों की जानकारी 'गोल्डन ऑवर' में मिल जाए, तो ९०% मामलों में पैसे बचाए जा सकते हैं।

राज्य में ५० साइबर लैब्स स्थापित की गई हैं और 'साइबर कॉर्पोरेशन' की स्थापना भी की गई है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में उन्होंने बताया-

बलात्कार के मामलों में ९८% आरोपियों की पहचान हो चुकी है।

ऐसे मामलों में ६० दिनों के भीतर फैसला आने की दर ९७.३% तक पहुंच चुकी है। महिलाओं पर अत्याचार के ९१% मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा हुआ है।

उपनगरीय रेल में बदलाव की मांग

फडणवीस ने कहा कि उपनगरीय ट्रेनों में दरवाजे नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री से मेट्रो जैसी वातानुकूलित और दरवाजे वाली डिब्बों की मांग की है। उन्होंने कहा-

जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और बिना किराया बढ़ाए ये डिब्बे यात्रियों को मिलेंगे।

ड्रग्स विरोधी कड़ी कार्रवाई

राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है।

२०१८ के अंत में १,५६८ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो २०२५ तक बढ़कर २,१९८ हो गए।

अब हर थाने में नार्कोटिक्स सेल की स्थापना की गई है।

जो अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग मामलों में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें केवल निलंबित नहीं बल्कि बर्खास्त किया जाएगा।

पीएम कुसुम योजना और ऊर्जा प्रगति

पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक राज्य में ६०% कृषि पंप लगाए जा चुके हैं, जिनमें से केवल तीन महीनों में ३.८६ लाख पंप लगाए गए। इससे २३ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिली है।

'प्रधानमंत्री सूर्य घर' योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाए जा रहे हैं।

जनसुरक्षा कानून पर स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा-

जन सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए ठोस और न्यायिक रूप से मान्य सबूत जरूरी होते हैं। किसी संगठन पर प्रतिबंध भी न्यायालय की निगरानी में होता है।

उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सिद्धांतों और लोकतंत्र का पूरी तरह पालन करते हुए यह कानून बनाया गया है।

लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा-

विधानसभा किसी विधायक, मंत्री या अधिकारी की नहीं, बल्कि राज्य की १४ करोड़ जनता की संपत्ति है। हाल में जो घटनाएं घटीं, वे दुखद हैं।

उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे- संसदीय परंपरा, भाषा और संवाद की त्रिसूत्रीय मर्यादा का पालन करें।

धारावी पुनर्विकास परियोजना पर स्पष्टीकरण

धारावी पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत झोपड़पट्टीवासियों का पुनर्वसन उसी क्षेत्र में किया जाएगा और वहां के उद्योगों को भी यथावत सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी ज़मीन अडानी को नहीं दी गई है। ये ज़मीन 'डीआरपी' (धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण) को सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने जवाब में राज्य के विकास, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र, और संसदीय शिष्टाचार जैसे मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी और महाराष्ट्र को सुरक्षित, विकसित और जवाबदेह प्रशासन देने का आश्वासन दिया।

मुंबई बनेगी 'क्रिएटिव इकोनॉमी' का वैश्विक केंद्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान

रिपोर्ट: विशेष प्रतिनिधि ।मुंबई, १८ जुलाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई देश की एंटरटेनमेंट कैपिटल है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'क्रिएटिव इकोनॉमी' को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की घोषणा की थी, जो अब साकार हो रही है।

वे १ से ४ मई तक मुंबई में आयोजित 'वेव्ज कॉन्क्लेव' के निष्कर्ष रिपोर्ट के प्रकाशन समारोह में बोल रहे थे। इसी अवसर पर उन्होंने 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी और छक्कछ कैंपस का उद्घाटन भी किया।

इस मौके पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, आईटी मंत्री एड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, केंद्रीय सचिव संजय जाजू, प्रसून जोशी, शेखर कपूर, साकेत मिश्रा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

वेव्ज इंडेक्स का महत्व और मुंबई की भूमिका

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि-

कुछ महीनों पहले क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़ा वेव्ज इंडेक्स ९३,००० करोड़ था, जो अब १ लाख करोड़ पार कर गया है।

राज्य सरकार क्रिएटर्स इकोनॉमी को और बल देने के लिए १५० करोड़ का विशेष फंड मंजूर करेगी।

उन्होंने कहा-खखउढ केवल एक प्रशिक्षण संस्था नहीं बल्कि एक आइकोनिक डेस्टिनेशन बनेगी, जहां लोग सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि देखने भी आएंगे। आनेवाली पीढ़ियों के लिए यह संस्थान क्रिएटिव इकोनॉमी का केंद्रबिंदु होगा।

वेव्ज कॉन्क्लेव अब हर साल या दो साल में मुंबई में नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का वक्तव्य

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-

यह केवल एक शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए खखढ-खखच् की तरह एक संपूर्ण शैक्षणिक श्रृंखला बने।

उन्होंने बताया कि-

खखउढ के लिए अब तक ४०० करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है।

मुंबई फिल्म सिटी में इसका बड़ा कैंपस बनेगा।

इसकी इमारत पर्यावरण और भूगोल के अनुसार डिज़ाइन की जाएगी।

उन्होंने बताया कि-

खखउढ का औपचारिक सहयोग गूगल, मेटा, एनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अडोबी जैसी वैश्विक कंपनियों से हुआ है।

इसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से भी समझौता किया गया है।

कोर्सेज उद्योग की ज़रूरतों के मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं।कोर्स और लक्ष्य

पहले साल में ३०० विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कोर्स की अवधि ३ महीने से लेकर २ वर्ष तक होगी।कोर्स में तक्नद्ध, गेमिंग, दठ, पोस्ट-प्रोडक्शन, एनीमेशन जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।

अन्य घोषणाएं प्रसार भारती और महाराष्ट्र फिल्म एंड डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ है ताकि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बल मिल सके।

खखउढ का लोगो भी इस अवसर पर लॉन्च किया गया। केंद्रीय सचिव संजय जाजू ने वेव्ज कॉन्क्लेव के निष्कर्षों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय मंत्री वैष्णव की मौजूदगी में हुई इस घोषणा से यह स्पष्ट हुआ कि मुंबई न केवल भारत की बल्कि विश्व की क्रिएटिव इकोनॉमी का नेतृत्व करेगी, और यहां स्थापित होनेवाला खखउढ आनेवाले समय में क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का हब बनेगा।

प्राचार्य सिद्दीकी नविद का सेवापूर्ती सत्कार समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न

रिपोर्ट: बीड़ से प्रतिनिधि

शहर के प्रतिष्ठित नॅशनल उर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीड़ के प्राचार्य सिद्दीकी नविद की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में एक भव्य सत्कार समारोह का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। यह समारोह उनके शिक्षा क्षेत्र में दिए गए ३० वर्षों से अधिक सेवा की सराहना और उनके अमूल्य योगदान को शुभकामनाएं देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिराजुद्दीन देशमुख ने की, जबकि प्रमुख अतिथियों के रूप में सुभाषचंद्रजी सारडा, डॉ. आदिति सुभाषचंद्रजी सारडा (संचालिका - आदित्य शिक्षण संस्था, बीड़), फरीदुद्दीन देशमुख (सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी) एवं परवेज युसुफ़जई नासेर खान (सदस्य, प्रियदर्शनी एजुकेशन ट्रस्ट, बीड़) विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का पारंपरिक रूप से शॉल और पुष्पहार देकर स्वागत किया गया। उसके बाद प्राचार्य सिद्दीकी नविद के शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने १९९४ से २०२१ तक सहशिक्षक के रूप में २५ वर्षों तक सेवाएं दीं और २०२१ से २०२५ तक प्राचार्य के पद पर रहते हुए संस्था की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

इस अवसर पर प्रियदर्शनी एजुकेशन ट्रस्ट बीड़ के अध्यक्ष व सचिव ने अपने भाषण में प्राचार्य सिद्दीकी नविद के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास किए, वे अनुकरणीय हैं। उन्होंने न केवल एक शिक्षक की भूमिका निभाई, बल्कि एक मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणास्रोत के रूप में कार्य किया। ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी उर्दू और मराठी माध्यम स्कूलों के मुख्याध्यापक, शिक्षकगण तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण इस आयोजन में उपस्थित रहे। प्राचार्य सिद्दीकी नविद को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर भव्य रूप से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का सफल संचालन शेख अब्दुल रहीम ने किया और आभार प्रदर्शन शेख ज़मीर ने व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में मुख्याध्यापक सिद्दीकी नदीमोद्दीन सहित पूरे विद्यालय स्टाफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्राचार्य सिद्दीकी नविद जैसे समर्पित और सजग शिक्षकों की सेवाएं वास्तव में समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। उनका शैक्षणिक दृष्टिकोण, अनुशासन, और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए की गई मेहनत हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। यह सत्कार समारोह न केवल एक शिक्षक के योगदान को सलाम था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह सीख भी देता है कि शिक्षा सेवा का सबसे सुंदर रूप है।

शिक्षक सम्मानित हों, तो शिक्षा मजबूत होती है।

आजी-माजी विधायक की जोड़ी होने के बावजूद बीड़ के सड़कों की हालत बदहाल!

नगर परिषद का अस्तित्व ही जैसे मिट गया-एस.एम.यूसुफ

बीड़ (प्रतिनिधि):

बीड़ विधानसभा क्षेत्र को पिछले कुछ वर्षों से एकजुट आजी-माजी (वर्तमान और पूर्व) विधायकों की जोड़ी मिली हुई है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन, इन दोनों की जोड़ी के बावजूद बीड़ शहर की सड़कों की समस्या हल नहीं हो पा रही है और बीड़ नगर परिषद का तो जैसे अस्तित्व ही खत्म हो गया है, ऐसा तीखा बयान मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ ने अपने प्रेस नोट में जारी किया है।

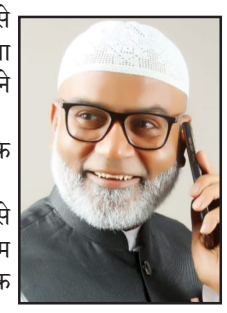

इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि -

छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर राजुरी वेस, कारंजा टॉवर, बलभीम चौक, जुना बाजार होकर चांदनी चौक तक की सड़क,

राजुरी वेस से बुंदलपुरा होकर कबाड़ गली, माळीवेस पुलिस चौकी तक की सड़क,

कारंजा टॉवर से जुनी भाजी मंडई होकर बुंदलपुरा तक की सड़क,

बलभीम चौक से धोंडीपुरा होकर माळीवेस चौक तक की सड़क -

ये सभी चारों प्रमुख सड़कें बेहद खस्ता हालत में पहुंच चुकी हैं।

इन सड़कों से गुजरते वक्त पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों को मानो नरक जैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इन सड़कों पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गड्ढे और उसमें जमा बरसात का पानी आम जनता को भारी तकलीफ दे रहा है।

विशेष बात यह है कि इस समय बीड़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और उनके विश्वासी माने जाने वाले पूर्व विधायक, यह जोड़ी सक्रिय है। फिर भी इन चार सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। और तो और, राजुरी वेस से बुंदलपुरा जाने वाली सड़क पर इन्हीं पूर्व विधायक का खुद का घर स्थित है।

जिस प्रकार किसी चीज़ की कीमत तब बढ़ती है जब दो शक्तियाँ एकसाथ मिलती हैं, उसी तरह बीड़ के मतदाताओं को भी उम्मीद थी कि जब मौजूदा विधायक के साथ पूर्व विधायक मिलेंगे तो विकास दुगना होगा।

लेकिन अब स्थिति यह है कि न केवल विधानसभा क्षेत्र, बल्कि खुद शहर की सड़कें और नालियां भी बदहाल हैं।

अब सवाल उठ रहा है कि यह सब बीड़ निवासियों की नासमझी है या फिर इन आजी-माजी विधायकों की निष्क्रियता?

नगर परिषद से न शहर की सफाई हो पा रही है और न ही अन्य विकास कार्यों की उम्मीद करना वाजिब लगता है। मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ ने इस प्रेस बयान में यह भी टिप्पणी की है कि बीते कुछ वर्षों में बीड़ नगर परिषद का अस्तित्व जैसे मिट चुका है और हर क्षेत्र में अंधकार छा गया है।

बीड नगरपालिका के सामने वाले सड़क का मालिक कौन?

प्रशासन पहले स्पष्ट करे-उल्हास गिराम

बीड (प्रतिनिधि):

बीड शहर के प्रमुख मार्गों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर राजुरी वेस तक की सड़क की हालत बदतर हो चुकी है। यह मार्ग नगरपालिका और जिला परिषद क्षेत्र में आता है, लेकिन इस सड़क पर जगह-जगह छोटे-बड़े सैकड़ों गड्ढे पड़ चुके हैं।

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) के जिला प्रमुख उल्हास गिराम ने जब इस सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर नगरपालिका से सवाल किया, तो उन्हें जवाब मिला कि यह सड़क हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग (झथऊ) के अंतर्गत आती है। जब यही प्रश्न झथऊसे किया गया, तो उन्होंने इसे नगरपालिका का मार्ग बताया।

इस भ्रम और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए उल्हास गिराम ने अपने पत्र में सवाल उठाया कि - आख़िर इस सड़क का असली मालिक कौन है? प्रशासन को पहले इस बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि सोमवार को वे इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं, और आने वाले एक महीने के भीतर यह सड़क पूरी तरह से नई बनाई जाए, इसके लिए वे लगातार पाठपुरावा (अनुवर्ती प्रयास) करेंगे। यह सड़क बीड शहर की मुख्य बाजार पेठ और कई प्रमुख शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों को जोड़ती है। आम नागरिकों के लिए यह एक जीवनरेखा जैसी सड़क है, लेकिन संबंधित विभागों के टालमटोल भरे जवाबों से लोगों में गुस्सा और नाराज़गी बढ़ रही है। उल्हास गिराम ने कहा कि प्रशासन आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चूंकि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार वर्तमान में जिले के संपर्क मंत्री हैं, इसलिए उन्हें इस सड़क की गंभीरता को समझते हुए इसका नवनिर्माण जल्द करवाना चाहिए। इसी संबंध में उन्हें एक आधिकारिक पत्र भेजा जाएगा।

मौलाना आज़ाद विचार मंच बीड़ द्वारा एम.एम.ए. चैंपियन शेख रबीअ अहमद का स्वागत समारोह

बीड़ (संवाददाता):

देशभर में सात राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले बीड़ की सरज़मीन के होनहार एम.एम.ए. फाइटर शेख रबीअ अहमद अब्दुर्रहीम का मौलाना आज़ाद विचार मंच बीड़ की ओर से भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम सय्यद मुमताज़ अली हाशमी के निवास पर आयोजित हुआ, जहां पूर्व विधायक सय्यद सलीम के हाथों स्वागत पत्र (सम्मान पत्र) भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मौलाना आज़ाद विचार मंच के ज़िला अध्यक्ष क़ाज़ी मुजीबुर्रहमान, सचिव अरशद सिद्दीक़ी सर, एडिटर जमाल नदीम, हज़रत नदीम मिर्ज़ा, सय्यद मुमताज़ अली हाशमी सर, हाजी एजाज़ बेग सर, ज़हीरुद्दीन ख़तीब सर, इर्फ़ान सिद्दीक़ी सर, क़ाज़ी शाकिर, शेख रबीअ अहमद, सय्यद अशआर मुमताज़ अली हाशमी एवं अन्य गणमान्य लोग विशेष रूप से मौजूद रहे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com